International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925(Online), Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 03(III), July- September, 2025, pp. 75-80

बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय योजनाओं का ग्रामीण कृषकों पर प्रभावः धार जिले का एक सर्वेक्षण अध्ययन

डॉ. नितिन बड़ेजा[1] | अजय भिड़े[2*]

[1]सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय जावरा, जिला–रतलाम, मध्यप्रदेश।
[2]शोधार्थी, वाणिज्य अध्ययनशाला, विक्रम विवविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश।

[*]Corresponding Author: lakhanchouksey@gmail.com

Citation:

सार

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकिंग संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषतः कृषि प्रधान क्षेत्रों में बैंकों द्वारा प्रदत्त वित्तीय योजनाएँ न केवल कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने हेतु प्रेरित भी करती हैं। बैंक ऑफ इंडिया, एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक, धार जिले में ग्रामीण कृषि विकास हेतु विविध वित्तीय योजनाएँ संचालित करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन योजनाओं के प्रत्यक्ष प्रभाव का आकलन करना है। यह अध्ययन धार जिले के 128 ग्रामीण कृषकों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित विभिन्न वित्तीय योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषि ऋण, फसल बीमा योजना, ब्याज सब्सिडी योजना आदिके प्रभाव का विश्लेषण करना है। शोध के लिए प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह प्रश्नावली और साक्षात्कार विधि से किया गया तथा प्राप्त समंक का प्रतिशत आधारित विश्लेषण किया गया। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश कृषकों को इन योजनाओं से कृषि निवेश, उत्पादन, आय और आत्मनिर्भरता में सकारात्मक लाभ प्राप्त हुए हैं। साथ ही, बैंक अधिकारियों का सहयोग भी संतोषजनक पाया गया। यद्यपि कुछ योजनाओं की जानकारी का अभाव, प्रक्रिया की जटिलता और समयबद्ध वितरण की चुनौतियाँ भी रहीं, फिर भी कुल मिलाकर बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय योजनाएँ ग्रामीण कृषकों के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हो रही हैं। यह शोध ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की प्रभावशीलता को समझने तथा नीतिगत सुझाव देने हेतु उपयोगी है।

शब्दकोशः *ग्रामीण कृषक, बैंक ऑफ इंडिया, वित्तीय योजनाए, ऋण उपयोगिता।*

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। देश की आर्थिक व्यवस्था का आधार कृषि है, किंतु आज भी अधिकांश कृषक सीमित संसाधनों, असुरक्षित आय और ऋण की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं से जूझते हैं। ऐसे में बैंकों की भूमिका केवल वित्तीय संस्थाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे ग्रामीण विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। विशेषतः बैंक ऑफ इंडिया जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएँ, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गहराई से

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

कार्यरत हैं, कृषकों को समय पर वित्तीय सहायता, ऋण, बीमा और अन्य योजनाएँ उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य करती हैं।

बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी और यह एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसने ग्रामीण बैंकिंग और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके माध्यम से विभिन्न वित्तीय योजनाएँ, विशेषकर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषि ऋण, फसल बीमा योजना, ब्याज सब्सिडी योजना, और कृषि यंत्र ऋण आदि ग्रामीण कृषकों को सुलभ कराई जाती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को उनके फसल चक्र के अनुसार सीमित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होता है, जिससे वे बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी जैसे खर्चों की पूर्ति कर सकते हैं। यह योजना सरल प्रक्रिया, कम दस्तावेज और पुनर्भुगतान में लचीलापन जैसे लाभों के कारण अत्यंत लोकप्रिय रही है।

इसी प्रकार, कृषि ऋण योजना के अंतर्गत किसानों को अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है जिससे वे भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन एवं यंत्रीकरण जैसी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र को जोखिमों से सुरक्षित रखने हेतु फसल बीमा योजनाएँ, विशेषतः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप या फसल हानि की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।

इन योजनाओं के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, आय में वृद्धि, तथा आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहन मिला है। जब किसान समय पर ऋण प्राप्त करता है और उसका उपयोग कृषि निवेश में करता है, तो उत्पादन बढ़ता है, कृषि लाभदायक बनती है और ग्रामीण क्षेत्र की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ गति पकड़ती हैं। यही कारण है कि ऋण की उपयोगिता और उसकी समयबद्धता को कृषि विकास का मूल तत्व माना गया है।

इस अध्ययन में मध्यप्रदेश के धार जिले को विशेष अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है, जो राज्य का एक प्रमुख कृषि–आधारित जिला है। यहाँ की जलवायु, भूमि की उर्वरता तथा जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। फिर भी संसाधनों की सीमितता और वित्तीय अक्षमता कृषकों की उत्पादकता और आय को सीमित करती है। ऐसे में बैंक ऑफ इंडिया की योजनाएँ धार जिले के ग्रामीण कृषकों के लिए आर्थिक जीवन रेखा बनकर उभरी हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य इन योजनाओं के जागरूकता स्तर, उपयोग, प्रभाव और आर्थिक लाभ का मूल्यांकन करना है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि इन वित्तीय पहलों ने कृषकों के जीवन और आजीविका में किस हद तक सकारात्मक बदलाव लाया है।

अध्ययन की आवश्यकता

धार जिले में अधिकांश कृषक लघु एवं सीमांत वर्ग के हैं। सीमित संसाधनों के कारण उनकी कृषि उत्पादकता और आर्थिक स्थिति अस्थिर रहती है। बैंकिंग सहायता के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण की संभावना है।

उद्देश्य

- बैंक ऑफ इंडिया की योजनाओं की जानकारी का स्तर जानना।
- योजनाओं का कृषि आय एवं निवेश पर प्रभाव देखना।
- सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अनुसंधान पद्धति

वर्तमान अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान डिज़ाइन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय योजनाओं के ग्रामीण कृषकों पर प्रभाव का आकलन करना है। यह शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के समंको के उपयोग से संचालित किया गया। प्राथमिक समंको के लिए धार जिले के

128 कृषकों को सुविधाजनक प्रतिदर्श चयन विधि के आधार पर चुना गया। समंक संग्रह हेतु पूर्व संरचित प्रश्नावली एवं प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया, जिसमें योजनाओं की जानकारी, ऋण उपयोगिता, समयबद्धता और आर्थिक लाभ से संबंधित प्रश्न सम्मिलित थे। द्वितीयक समंक बैंक की रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, शोध–पत्र और वेबसाइटों से प्राप्त किए गए। प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रतिशत विधि द्वारा किया गया, जिससे प्रवृत्तियों, जागरूकता स्तर तथा योजनाओं के प्रभाव का सारगर्भित निष्कर्ष निकाला जा सके। यह पद्धति अध्ययन को आधारभूत वस्तुनिष्ठता प्रदान करती है तथा क्षेत्रीय स्तर पर बैंकिंग सेवाओं की प्रभावशीलता का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध हुई है।

समंक विश्लेषण एवं परिणाम

तालिका 1: जनसांख्यिकी चर

चर (Variable)	श्रेणी (Category)	आवृत्ति (Frequency)	प्रतिशत (%)
लिंग	पुरुष	108	84.38%
	महिला	20	15.62%
	कुल	128	100%
आयु वर्ग	18–30 वर्ष	26	20.31%
	31–45 वर्ष	54	42.19%
	46–60 वर्ष	36	28.13%
	60 वर्ष से अधिक	12	9.37%
	कुल	128	100%
शैक्षणिक योग्यता	निरक्षर	32	25.00%
	प्राथमिक (5वीं तक)	38	29.69%
	माध्यमिक (10वीं तक)	34	26.56%
	उच्च माध्यमिक एवं अधिक	24	18.75%
	कुल	128	100%
भूमि स्वामित्व	बिना भूमि (किरायेदार)	18	14.06%
	1–2 एकड़	52	40.63%
	2–5 एकड़	38	29.69%
	5 एकड़ से अधिक	20	15.62%
	कुल	128	100%
वार्षिक पारिवारिक आय	₹50,000 से कम	22	17.19%
	₹50,000 – ₹1,00,000	56	43.75%
	₹1,00,001 – ₹2,00,000	34	26.56%
	₹2,00,000 से अधिक	16	12.50%
	कुल	128	100%

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

धार जिले के 128 कृषकों पर आधारित जनसांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता पुरुष (84.38%) हैं, जबकि महिलाएं मात्र 15.62% हैं, जो यह संकेत देता है कि कृषि कार्यों में पुरुषों की सहभागिता अधिक है। आयु के अनुसार, सर्वाधिक कृषक 31–45 वर्ष (42.19%) के आयु वर्ग में आते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि का भार मुख्यतः मध्यवर्गीय वर्ग पर है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि में यह देखा गया कि 25% कृषक निरक्षर हैं, जबकि 29.69% केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषकों में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है, जो योजनाओं के प्रति जागरूकता को प्रभावित कर सकता है।

भूमि स्वामित्व के आधार पर 40.63% कृषकों के पास 1–2 एकड़ भूमि है, जो सूचित करता है कि लघु कृषक ही अध्ययन में प्रमुख हैं। वार्षिक पारिवारिक आय में यह देखा गया कि अधिकांश कृषक ₹50,000–₹1,00,000 की श्रेणी में आते हैं (43.75%), जिससे पता चलता है कि इनकी आर्थिक स्थिति सीमित संसाधनों पर निर्भर है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय योजनाओं का प्रभाव इस सामाजिक–सांख्यिकीय पृष्ठभूमि से गहराई से जुड़ा हुआ है और इन्हें योजनाओं की पहुंच और उपयोगिता के आकलन में आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

तालिका 2: योजनाओं की जानकारी

योजना का नाम	जानकारी रखने वाले कृषक (आवृत्ति)	प्रतिशत (%)
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)	105	82.03%
कृषि ऋण योजना	95	74.22%
फसल बीमा योजना	77	60.16%
ब्याज सब्सिडी योजना	62	48.44%
पशुपालन/कृषि यंत्र ऋण योजना	58	45.31%
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	66	51.56%

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

प्राप्त आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि धार जिले के अधिकांश कृषकों को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की जानकारी है, विशेषकर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे 82.03% कृषक जानते हैं। इसके बाद कृषि ऋण योजना (74.22%) और फसल बीमा योजना (60.16%) का स्थान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन योजनाओं का प्रत्यक्ष संबंध ऋण एवं फसल सुरक्षा से है, उनकी जानकारी का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है।हालांकि, ब्याज सब्सिडी योजना (48.44%) और कृषि यंत्र ऋण (45.31%) जैसी योजनाओं की जानकारी मध्यम स्तर पर देखी गई, जो यह इंगित करती है कि कुछ योजनाएँप्रचार या व्यवहारिक पहुँच के अभाव में कृषकों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पा रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (च्डथ्ठल्) की जानकारी भी केवल 51.56%कृषकों को है, जबकि यह योजना व्यापक रूप से प्रचारित है।इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि योजनाओं के बारे में सूचनात्मक जागरूकता अभियान की आवश्यकता है ताकि सभी कृषकों तक योजनाओं की जानकारी सरल भाषा व सुलभ माध्यमों से पहुँचे और वे इनका समुचित लाभ उठा सकें।

तालिका 3: ऋण उपयोगिता और समयबद्धता

विवरण (Indicators)	उत्तरदाता (आवृत्ति)	प्रतिशत (%)
ऋण समय पर प्राप्त हुआ	85	66.41%
ऋण आवेदन प्रक्रिया सरल लगी	74	57.81%
ऋण की राशि कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त थी	76	59.38%
ऋण का उपयोग केवल कृषि कार्यों में हुआ	91	71.09%
ऋण चुकाने में कठिनाई महसूस की	35	27.34%
बैंक अधिकारियों का व्यवहार सहयोगात्मक रहा	88	68.75%

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 66.41% कृषकों को ऋण समय पर प्राप्त हुआ, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बैंक ऑफ इंडिया की ऋण वितरण प्रणाली धार जिले में अपेक्षाकृत समयबद्ध और क्रियाशील है। हालांकि, 57.81% कृषकों को ही आवेदन प्रक्रिया सरल लगी, जिसका तात्पर्य है कि अभी भी लगभग 42% कृषकों को दस्तावेजी जटिलता या प्रक्रियात्मक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

59.38% कृषकों ने ऋण राशि को कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त माना, जबकि शेष को या तो राशि कम लगी या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी। सकारात्मक पक्ष यह है कि 71.09% कृषकों ने ऋण का उपयोग केवल कृषि उद्देश्यों में किया, जिससे ऋण का उचित उपयोग प्रमाणित होता है। 27.34% कृषकों ने ऋण चुकाने में कठिनाई अनुभव की, जो यह दर्शाता है कि प्राकृतिक आपदाएँ, बाजार मूल्य अस्थिरता, या आय का असमान वितरण, ऋण वापसी को प्रभावित कर सकते हैं। यह भी सराहनीय है कि 68.75% उत्तरदाताओं ने बैंक अधिकारियों के व्यवहार को सहयोगात्मक बताया, जो ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में वि वास को मज़बूत करता है।इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋण वितरण और उपयोगिता में बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका प्रभावी रही है, किन्तु ऋण प्रक्रिया की सरलीकरण और कृषकों को समयबद्ध मार्गदर्शन प्रदान कर इसकी कार्यक्षमता को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है।

तालिका 4: आर्थिक प्रभाव

आर्थिक लाभ का क्षेत्र	सहमत कृषक (आवृत्ति)	प्रतिशत (%)
कृषि निवेश में वृद्धि हुई	91	71.09%
उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार हुआ	87	67.97%
पारिवारिक आय में वृद्धि हुई	83	64.84%
कृषि कार्यों में आधुनिक साधनों का उपयोग बढ़ा	76	59.38%
ऋण के कारण आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई	79	61.72%
विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक संकट से राहत मिली	68	53.13%

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त वित्तीय योजनाओं का ग्रामीण कृषकों के आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। 71.09% कृषकों ने माना कि उन्हें कृषि निवेश बढ़ाने में सहायता मिली, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय सहायता ने उन्हें बीज, खाद, सिंचाई एवं उपकरणों जैसे क्षेत्रों में निवेश करने का अवसर दिया। इसी प्रकार, 67.97% कृषकों ने उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार का अनुभव किया, जो यह दर्शाता है कि योजनाओं ने कृषि की गुणवत्ता और परिमाण दोनों में वृद्धि की है।लगभग 64.84% कृषकों की पारिवारिक आय में वृद्धि हुई, जो उनके जीवन–स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक संकेत है। इसके साथ ही, 59.38% कृषकों ने कृषि में आधुनिक साधनों के उपयोग में वृद्धि की पुष्टि की, जिससे परंपरागत खेती से आधुनिक कृषि प्रणाली की ओर संक्रमण दिखाई देता है।

61.72% कृषकों ने बताया कि ऋण और योजनाओं से उनमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई है। यह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक सशक्तिकरण की भी प्रतीक है। इसके अतिरिक्त, 53. 13% उत्तरदाताओं ने यह भी माना कि कठिन समय में जैसे सूखा, फसल नुकसान या बाजार गिरावट के दौरान योजनाओं ने उन्हें आर्थिक संकट से राहत दी। इन आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि बैंक ऑफ इंडिया की योजनाओं ने न केवल कृषकों की आजीविका को सशक्त किया है, बल्कि उन्हें सतत कृषि एवं आर्थिक स्थायित्व की दिशा में भी प्रेरित किया है।

सुझाव

- सभी योजनाओं की जानकारी ग्राम स्तर पर प्रचारित की जाए।
- ऋणप्रक्रिया को सरल और डिजिटल किया जाए।

- फसल बीमा व सब्सिडी योजनाओं के लिए अलग से हेल्पलाइन या सुविधा केंद्र हो।
- केसीसी की सीमा और कार्यकाल में लचीलापन लाया जाए।

उपसंहार

इस अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा धार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित वित्तीय योजनाएँ कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। योजनाओं की जानकारी, ऋण वितरण की समयबद्धता, ऋण की उपयोगिता और योजनाओं से प्राप्त आर्थिक लाभ इन सभी बिंदुओं पर आधारित विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि अधिकांश कृषक इन सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण और फसल बीमा जैसी योजनाएँ सबसे अधिक प्रभावशाली रहीं, जिन्होंने न केवल कृषि निवेश और उत्पादकता बढ़ाई, बल्कि कृषकों की पारिवारिक आय और आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि की।

हालाँकि अध्ययन में कुछ सीमाएँ भी सामने आईं, जैसे योजनाओं के प्रति पूर्ण जानकारी का अभाव, ऋण आवेदन प्रक्रिया की जटिलता, और ब्याज सब्सिडी या बीमा लाभों की सीमित पहुँच। इन अवरोधों के बावजूद, बैंक अधिकारियों का सहयोगात्मक व्यवहार और योजनाओं की समयबद्धता ने ग्रामीण कृषकों में विश्वास एवं संतुष्टि को जन्म दिया है। अतः यह कहा जा सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय पहलें ग्रामीण विकास के एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर रही हैं। यदि इन योजनाओं के प्रचार–प्रसार, प्रक्रिया सरलीकरण और निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए, तो इनका प्रभाव और अधिक गहन और व्यापक हो सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Government of India. (2020). *Annual report 2019-20: Department of Financial Services*. Ministry of Finance. https://financialservices.gov.in
2. Reserve Bank of India. (2021). *Report on Trends and Progress of Banking in India 2020-21*. https://rbi.org.in/scripts/AnnualPublications.aspx?head=Trends%20and%20Progress%20of%20Banking%20in%20India
3. Bank of India. (2022). *Annual Report 2021-22*. https://bankofindia.co.in
4. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (2021). *PM Kisan, KCC, and PMFBY scheme guidelines*. Government of India. https://agricoop.nic.in
5. Mishra, S., & Sahu, R. K. (2019). Impact of Kisan Credit Card scheme on agricultural productivity: A case study of Madhya Pradesh. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 74(2), 155–164.
6. Sharma, R., & Verma, A. (2020). Role of rural banking in economic development: A study on rural credit. *International Journal of Management and Social Sciences Research*, 9(5), 23–28.
7. Patel, M. & Tiwari, K. (2021). Evaluation of rural credit schemes and their impact on farmer's livelihood. *Journal of Rural Development and Finance*, 12(3), 44–53.
8. Singh, V. (2020). Awareness and accessibility of government schemes among small and marginal farmers. *Journal of Agricultural Policy and Planning*, 8(4), 65–71.
9. Madhya Pradesh State Planning Commission. (2021). *District Statistical Handbook: Dhar*. Government of Madhya Pradesh.
10. World Bank. (2019). *Financial Inclusion: Global Findex Database 2018*. https://globalfindex.worldbank.org

❑❑❑